

संपादकीय

आपराधिक लापरवाही की जवाबदेही हो तय

दिल्ली में मालवीय नगर स्थित एक होटल में हुए अग्निकांड के बाद भले ही गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया हो, लेकिन सवाल है कि अग्निकांड में मरे लोगों का जीवन कौन लौटाएगा? आखिर देश की राजधानी में अक्सर होने वाले अग्निकांडों का सिलसिला कब और कैसे खत्म होगा? क्या इस आपराधिक लापरवाही की जवाबदेही तय होगी? एक बार फिर अंधे लालच और आंख मूंदे तंत्र की लापरवाही से बुधवार को एक होटल में लगी भीषण आग में 21 लोगों की मौत हो गई। अभी भी कई लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका भी जतायी जा रही है। घटना ने एक बार फिर होटल, गेस्टहाउस और रेस्तरां संचालन की निगरानी करने वाली व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विडंबना देखिए कि मरने वालों में अधिकांश विदेशी लोग भी हैं, जो सस्ता इलाज कराने भारत आए थे। एक ही परिवार के आठ लोगों के अग्निकांड का शिकार होना बेहद दुःखद है। विडंबना देखिए कि जिस एक मंजिला भवन को छह कमरों का गेस्ट हाउस चलाने की अनुमति मिली थी, वहां शासन-प्रशासन की नाक के नीचे एक छह मंजिला होटल बना दिया गया, जिसमें 26 कमरे और रेस्टोरेंट संचालित किया जा रहा था। जिसमें अस्सी से सौ लोगों की मौजूदगी बतायी जा रही है। निश्चित रूप से यह महज आग से जुड़ा हादसा नहीं है बल्कि होटल संचालन से जुड़े नियमों की अनदेखी, निगरानी करने वाले विभागों की लापरवाही और तंत्र की विफलता का परिचायक है। लेकिन गाहे-बगाहे होने वाले अग्निकांडों के बावजूद तंत्र की काहिली बदस्तूर जारी है। जांच के दायरे में घटना के बाद फरार होटल मालिक ही नहीं, बल्कि वे अधिकारी भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने इसको संचालित करने के नियमों का अनुपालन नहीं किया और भवन निर्माण की स्वीकृति व उपयोग की अनुमति दी। यह जानते हुए भी कि होटल में निकासी का मार्ग बेहद संकरा है और अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध नहीं हैं। दिल्ली के होटल में हुए अग्निकांड के बारे में बताते हैं कि आपातकालीन निकासी के अभाव व सुरक्षा मानकों का पालन न होने से ज्यादा मौतें हुई। थुंआ निकलने की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण भी ज्यादा लोग दम घुटने से मौत के मुंह में समा गए। आखिर प्रशासन के अधिकारियों ने यह क्यों नहीं देखा कि स्वीकृत क्षमता से चार गुना विस्तार कर लिया गया है। गेस्ट हाउस के निर्माण में तमाम लाइसेंस शर्तों का घोर उल्लंघन हुआ। आपातकालीन निकासी की व्यवस्था न होने के कारण लोग अपनी जान बचाने के लिये, बदहवासी में ऊपरी मंजिलों से कूदते नजर आए। होटल के बाहर फैले बिजली के तार और अग्निकांड में हुई व्यापक क्षति बताती है कि विद्युत सुरक्षा मानकों का भी पालन ठीक से नहीं हुआ। जाहिर बात है कि गेस्ट हाउस से होटल बनाने से, उपयोग में हुए बदलाव की निगरानी की जिम्मेदारी स्थानीय नगर निकाय की होती है। यदि वर्षों से यह अवैध रूप से संचालित था, तो जांच व कार्रवाई क्यों नहीं की गई। यदि इसकी अगिन सुरक्षा को लेकर एनफोसी जारी की भी गई थी तो उसके बाद निरीक्षण व नियमों का अनुपालन क्यों सुनिश्चित नहीं किया गया? जाहिर बात है कि लाइसेंस प्राप्त करने वाले होटलों व रेस्टोरेंट की नियमित जांच करके इनके मालिकों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जानी चाहिए थी। क्यों किसी भी विभाग ने निरीक्षण व कार्रवाई की जहमत नहीं उठायी? क्या निरीक्षण करने वाले अधिकारी ले-देकर खामोश होकर बैठ गए? विडंबना देखिए कि बेसमेंट में कमरे,किचन बना दिए गए, लेकिन वेंटिलेशन व इमरजेंसी एजिजेंट का कोई प्रावधान नहीं था। जिससे होटल थुंआ निकासी की चिमनी बनकर रह गया और भवन लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। बताते हैं कि आरोपी होटल मालिक आपसपास में ही कुछ पार्टनरों के साथ मिलकर तीन होटल संचालित कर रहा था और सब ही जगह आपराधिक लापरवाही नजर आई। मोटे मुनाफे के लिये लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा था। लेकिन स्थानीय प्रशासन व जवाबदेह विभाग बेपरवाह बने रहें। निश्चय ही यह स्थिति सख्त कार्रवाई के बाद बदलनी चाहिए।

अभियान

अंबुबाची महापर्व: जब मातृशक्ति के सम्मान में ठहर जाता है पूरा शक्तिपीठ

भारत की आध्यात्मिक परंपराएं केवल पूजा-पूज और धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे प्रकृति, सृष्टि और जीवन के गहन रहस्यों से भी जुड़ी हुई हैं। इन्हीं अद्भुत परंपराओं में से एक है अंबुबाची महापर्व, जो अरुम के गुवाहाटी स्थित कामाख्या धाम में प्रतिवर्ष अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ आयोजन नहीं, बल्कि स्त्री शक्ति, सृजन क्षमता और प्रकृति के चक्रों के प्रति सम्मान व्यक्त करने वाला अद्वितीय उत्सव है। देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु, साधु-संत, तंत्रिक, शोधकर्ता और पर्यटक इस अवसर पर कामाख्या धाम पहुंचते हैं और इस रहस्यमयी परंपरा के साक्षी बनते हैं। नीलचल पर्वत पर स्थित कामाख्या मंदिर भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब भगवान शिव माता सती के मृत शरीर को लेकर तंडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को खंडित कर दिया। जहां-जहां उनके अंग गिरे, वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। माना जाता है कि कामाख्या धाम वह स्थान है जहां माता सती का येनिभाग गिरा था। यही कारण है कि यह मंदिर स्त्री शक्ति, सृजन और मातृत्व का प्रतीक माना जाता है।

“

सुप्रीम कोर्ट ने गत 27 मई को सीबीएसई की उस नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई है, जिसमें 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए दो भारतीय मूल भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया गया है।

प्रेरणा

“

जीवन की यात्रा में मनुष्य अनेक प्रकार की परिस्थितियों का सामना करता है। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिनमें धैर्य, समझदारी और लचीलापन अपनकर आसानी से आगे बढ़ा जा सकता है, जबकि कुछ लोग इन्हीं परिस्थितियों को अपने अहंकार और जित के कारण संघर्ष का मैदान बना देते हैं। दुर्भाग्य यह है कि ऐसे संघर्षों में अक्सर किसी की वास्तविक जीत नहीं होती। जो व्यक्ति स्वयं को विजेता समझता है, वह भी किसी न किसी रूप में हानि उठाता है। इसलिए कहा जाता है कि हर टकराव में शक्ति नहीं होती, बल्कि कई बार समझदारी से रास्ता छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत साबित होती है। एक छोटी नदी के ऊपर रखा गया एक संकरा लट्ठा इस सत्य को बहुत सरलता से समझाता है। उस लट्ठे से एक समय में केवल एक ही प्राणी सुरक्षित रूप से गुजर सकता था। एक दिन दो बकरे विपरीत दिशाओं से उस पर चढ़ गए। दोनों चलते-चलते बीच में पहुंच गए और आमने-सामने खड़े हो गए। अब स्थिति ऐसी थी कि यदि उनमें से कोई एक अपने अहंकार को प्राथमिकता दे तो मित्रता समाप्त होने में देर नहीं लगती। कई बार लोगों वीरों बाद महसूस करते हैं कि जिस बात के लिए उन्होंने संबंध तोड़ा था, वह वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण थी ही नहीं। व्यापार और पेशेवर जीवन में भी यही स्थिति देखने को मिलती है। सफल संस्थान वही होते हैं जहाँ संवाद और सहयोग को धकका देना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे उनका क्रोध बढ़ता गया और संघर्ष तीव्र हो गया। अंततः संतुलन बिगड़ा और दोनों नदी में गिर पड़े। कुछ क्षण पहले तक जो अपने आपको विजेता साबित कर रहा चाहते थे, वे दोनों ही विनाश का शिकार बन गए। यह लोग केवल पशुओं की कहानी नहीं है। यह मानव समाज का

त्रिभाषा विवाद के यक्ष प्रश्न व कोर्ट से उम्मीदें

नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में भाषाओं के अध्ययन से जुड़े कुछ सबसे महत्वपूर्ण सवाल उच्चतम न्यायालय के सामने उठे हैं। इनके पीछे दक्षिण में हिंदी बनाम विदेशी भाषा के मसले भी हैं। अभिभावकों की व्यावहारिक समस्याएं, विद्यालयों के पास उपलब्ध संसाधनों और अध्यापकों की संख्या जैसे सवालों का पिटारा भी अब खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गत 27 मई को सीबीएसई की उस नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई है, जिसमें 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए दो भारतीय मूल भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया गया है। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और विपुल ज्म पंचोली की पीठ ने इस मामले में कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया है, पर उन्होंने केंद्र सरकार, सीबीएसई और एनबीईआरटी को नोटिस जारी करके दो सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब मांगा है। अदालत ने अलबत्ता यह कहा है कि बोर्ड का तीसरी भाषा को शामिल करने का निर्णय सिद्धांत रूप में ‘प्रशंसनीय’ हो सकता है, लेकिन इसे वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से लागू करने में कुछ व्यावहारिक प्रश्न उठेंगे। शिक्षकों और पुस्तकों की कमी के मद्देनजर इस नीति को लागू करने की तार्किक और तथ्यात्मक चुनौतियों को लेकर अदालत अधिक चिंतित है।

बहरहाल, न्यायालय 15 और 16 जुलाई को दलीलें सुनेगा। उसी समय इस आदेश को लागू किया जा रहा होगा। शैक्षिक-प्रश्न के अलावा यह राजनीतिक प्रश्न भी है। अपनी भाषा-नीति के अनुरूप डोमपके ने इस कदम का विरोध किया है, वहीं कांग्रेस ने विधान परामर्श के अधिसूचना जारी होने की आलोचना की है। दक्षिण भारत, खासतौर से तमिलनाडु में कहा जा रहा है कि सीबीएसई का यह आदेश हिंदी थोपने का प्रयास है।

यह एक सजीव चित्र है। आज हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि अधिकांश विवादों की जड़ में कोई बड़ी समस्या नहीं होती। अक्सर छोटी-सी बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया जाता है। लोग समाधान खोजने के बजाय अपनी बात मनवाने में लग जाते हैं। परिणामस्वरूप एक साधारण मतभेद गंभीर संघर्ष में बदल जाता है। परिार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। घरों में कई बार छोटी-छोटी बातों को लेकर मतभेद हो जाते हैं। यदि परिवार का कोई सदस्य धैर्य से काम ले और स्थिति को समझने का प्रयास करे तो विवाद तुरंत समाप्त हो सकता है। लेकिन जब दोनों पक्ष स्वयं को सही साबित करने में लग जाते हैं, तब संबंधों में दरार पड़ने लगती है। वर्षों का प्रेम और विश्वास कुछ क्षणों की जित के कारण कमजोर पड़ जाता है। मित्रता के संबंध भी इसी परीक्षा से गुजरते हैं। दो घनिष्ट मित्र किसी मुद्दे पर असहमत हो सकते हैं, लेकिन यदि वे एक-दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें तो संबंध और मजबूत हो सकते हैं। इसके विपरीत यदि वे अपने अहंकार को प्राथमिकता देें तो मित्रता समाप्त होने में देर नहीं लगती। कई बार लोगों वीरों बाद महसूस करते हैं कि जिस बात के लिए उन्होंने संबंध तोड़ा था, वह वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण थी ही नहीं। व्यापार और पेशेवर जीवन में भी यही स्थिति देखने को मिलती है। सफल संस्थान वही होते हैं जहाँ संवाद और सहयोग को धकका देना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे उनका क्रोध बढ़ता गया और संघर्ष तीव्र हो गया। अंततः संतुलन बिगड़ा और दोनों नदी में गिर पड़े। कुछ क्षण पहले तक जो अपने आपको विजेता साबित कर रहा चाहते थे, वे दोनों ही विनाश का शिकार बन गए। यह लोग केवल पशुओं की कहानी नहीं है। यह मानव समाज का

“

कुछ समय पहले, सीबीएसई ने घोषणा की थी कि तीसरी भाषा की अनिवार्यता को 2029-30 शैक्षणिक वर्ष तक स्थगित कर दिया जाएगा। यह अचानक बदलाव क्यों? एनईपी 2020, जिसके तहत यह आदेश लागू किया जा रहा है, लचीलेपन का वादा करती है। वह गारंटी देती है कि किसी भी छात्र या राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। दूसरी तरफ अभिभावक और शिक्षक बोर्ड परीक्षाओं से ठीक पहले छात्रों पर बढ़ते दबाव को लेकर चिंतित हैं। प्रशिक्षित भाषा शिक्षकों की कमी और उपयुक्त पाठ्य-पुस्तकों की अनुपलब्धता भी चुनौतियाँ हैं। इस आदेश के विरोधी यह भी कहते हैं कि इससे विदेशी भाषा की पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों का अहित होगा। कुछ छात्र पहले से ही फ्रेंच, जर्मन या जापानी जैसी विदेशी भाषाओं का अध्ययन कर रहे हैं। वहीं इस नीति के समर्थक कहते हैं कि स्कूली शिक्षा भारतीय भाषाओं से ऊपर विदेशी भाषाओं को रखना न तो तार्किक है और न ही लाभकारी। विदेशी

भाषाओं को वैकल्पिक विषयों के रूप में पढ़ाया जा सकता है। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना, विदेशी भाषाओं को हतोत्साहित करना नहीं है। याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में कहा कि यह मुद्दा संघवाद और भाषा के चयन से जुड़े संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा है। भाषा व्यक्तिगत पसंद का विषय है और इसे थोपा नहीं जा सकता। इस पर पीठ ने कहा कि इस तर्क को उलट कर यह कहा जा सकता है कि अधिक भाषाएं सीखना, संघवाद की भावना को लाभ पहुंचाने का काम करेगा। 15 मई को जारी परिपत्र के अनुसार, विदेशी भाषा का चयन करने वाले छात्र दो भाषाओं में से एक चुन सकते हैं। यदि छात्र विदेशी भाषा का चयन करने वाले छात्र दो भाषाओं का अध्ययन करने के बाद केवल तीसरी भाषा के रूप में या एक अतिरिक्त चौथी भाषा के रूप में ही ऐसा कर सकेंगे। यह नियम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2023 का हिस्सा है। परिपत्र के अनुसार कक्षा 10 में तीसरी भाषा के लिए कोई बोर्ड

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

धोलेरा की ऊसर भूमि में ‘ड्रम प्लांटेशन’ के अभिनव प्रयोग से खिल उठी हरियाली

► **क्षारीय और बंजर भूमि तथा सूखे जैसे मुश्किल हालात में भी पौधे एक वर्ष में 12 फीट तक बढ़ गए**
► **मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में औद्योगिक विकास के साथ-साथ धोलेरा को विश्व स्तरीय टिकाऊ शहर के रूप में विकसित करने के साथ-साथ यहां हरित क्षेत्र बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है**
► **डीएसआईआरडीए ने इस प्रयोग के लिए गुजरात वन विभाग को दिया फंड**
► **इस अभिनव प्रयोग को मिली सफलता के बाद क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने के ठोस प्रयास किए जा रहे हैं**
► **इस वर्ष अतिरिक्त 20 हेक्टेयर क्षेत्र में इसी प्रकार से पौधरोपण शुरू किया गया है**

गांधीनगर : गर्मी की चिलचिलाती धूप में अहमदाबाद जिले के समुद्र तट के निरुद्विग्न धोलेरा में यात्रा करना एक बहुत ही कठिन अनुभव होता है। आग बरसाती सूर्य की किरणों के साथ ही ऊसर और बंजर समतल भूमि के कारण अर्ध-शुष्क जलवायु वाले इस क्षेत्र में खुले में जीवन सचमुच एक चुनौती बन जाता है। इसके बावजूद, वन विभाग ने इन कठिन परिस्थितियों के बीच ब्लॉक नं. 29 में एक अभिनव प्रयोग करके एक हरियाला वन विकसित किया है, जो इस रण यानी रेगिस्तानी क्षेत्र में मुगमर्षिका जैसा नजर आता है। धोलेरा की क्षारीय और खारी भूमि पर

गुजरात वन विभाग के अहमदाबाद (सामाजिक वनीकरण) विभाग द्वारा विकसित की गई नवीन ‘ड्रम प्लांटेशन’ पद्धति से 3200 से अधिक पौधे रोपे गए हैं। कठिन जलवायु की चुनौतियों की बीच भी इस प्रयोग से पौधे उगाने में तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक शहर धोलेरा में हरित क्षेत्र बढ़ाने के उद्देश्य से इस प्रोजेक्ट को धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण (डीएसआईआरडीए) द्वारा फंड किया गया है। देश के सेमीकंडक्टर मैनुफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहे धोलेरा में यह



हरित क्षेत्र टिकाऊ विकास का प्रतीक बन गया है। अत्यंत लवणीय यानी खारी भूमि और कठिन जलवायु में, जहां प्राकृतिक रूप से घास भी नहीं उग पाती, वहां इस पहल को मिली सफलता का विशेष महत्व है। **प्रायोगिक स्तर पर 3200 पौधों को उगाने में मिली सफलता** वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार अगस्त-2025 में 15 किस्म के 3200 से अधिक पौधों को प्लास्टिक के ड्रमों का उपयोग करके रोपा गया था। इस

प्रयोग का उद्देश्य पौधों की जड़ों को ऊंचाई पर रखकर भूमि के खारेपन से सुरक्षित रखना था। उल्लेखनीय बात यह है कि एक वर्ष से भी कम समय में, बहुत से पौधे 12 फीट तक ऊंचे हो गए हैं, जो इस क्षेत्र के लिए एक शानदार उपलब्धि है। अहमदाबाद सामाजिक वनीकरण विभाग की उप वन संरक्षक (डीसीएफ) डॉ. मीनल जानी ने कहा, “इस बंजर और लवणीय भूमि में पौधे लगाना अनेक प्रकार से चुनौतीपूर्ण कार्य था।

मिट्टी में विद्युत चालकता (इलेक्ट्रो-कंडक्टिविटी) बहुत ऊंची थी, कार्बन की मात्रा काफी कम थी और खारापन भी बहुत अधिक था। इसके अलावा, इस क्षेत्र में छह महीने तक पानी भरा रहता है, जिससे पौधों का विकास लगभग असंभव हो जाता था। इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमने ड्रम प्लांटेशन तकनीक अपनाई, जिसमें पौधों को ड्रम के भीतर ऊंचाई पर रोपा गया। इन ड्रमों में रेंती, पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी, वर्मी कम्पोस्ट, फसलों के



अवशेष और कोकोपीट भरे गए।” डॉ. मीनल जानी ने आगे कहा, “ड्रम के दोनों ओर हवा के आने-जाने के लिए छिद्र बनाए गए और उन्हें जमीन में लगभग एक फुट की गहराई पर दबा दिया गया। डीएसआईआरडीए ने आवश्यक मीठा पानी सुलभ कराया। सभी पौधों के लिए टपक सिंचाई (ड्रिप इरिगेशन) की व्यवस्था की गई। इन सभी प्रयासों के कारण, आज लगभग सभी पौधे जीवंत हैं और कड़ियों में तो फल भी आने लगे हैं। जिसके चलते यहां परागण करने वाले जीव-जंतु और पक्षी चहचहा रहे हैं।”

15 से अधिक प्रजातियों के पौधे रोपे गए इस क्षेत्र को हरा-भरा बनाने के लिए यहां 15 से अधिक प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं, जिनमें पीलू (मेसवक), पलाश, सेमल, पारस पीपल, बरगद, पीपल, पीला गुलमोहर, देसी बबूल,

करंज, अर्जुन, जंगल जलेबी, नीम, लिसोड्रा या गुंदा और इमली शामिल हैं। **एक नया इकोसिस्टम बना, पोलिनेटर्स और पक्षियों की चहचहाहट से गूंज उठा क्षेत्र** डॉ. मीनल जानी ने कहा, “जहां कभी घास का तिनका भी नहीं उग पाता था, अब वहां भूमि की स्थिति में सुधार के कारण परागण करने वाले जीव-जंतु (पोलिनेटर्स), पक्षी और प्राकृतिक रूप से उगने वाली घास दिखाई दे रही है।” अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि बुवाई की प्रक्रिया में उपयोग में लिए गए प्लास्टिक के ड्रमों को बाद में हटाकर रिसाइकिल किया जाएगा, ताकि यह प्रोजेक्ट पर्यावरण की दृष्टि से पूरी तरह टिकाऊ बना रहे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का विजन धोलेराविशेष निवेशक्षेत्र (एसआईआर) को टिकाऊ औद्योगिकीकरण के लिए वैश्विक मानक के तौर पर विकसित

मानसून से पहले प्रशासन अलर्ट, जनकल्याण अभियानों की समीक्षा में इंचार्ज सचिव ने तय की कार्ययोजना

वडोदरा। आगामी मानसून, स्वच्छता अभियान और विभिन्न जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को लेकर वडोदरा जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। राज्य सरकार की प्राथमिक योजनाओं और अभियानों की प्रगति की समीक्षा के लिए गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के इंचार्ज सचिव पी. स्वरूप ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। बैठक में विशेष रूप से स्वच्छता अभियान, आपदा प्रबंधन, स्कूल प्रवेशोत्सव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुरासन के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों पर फोकस किया गया।



जाएगा। प्रशासन का प्रयास है कि केवल पौधे लगाए ही न जाएं, बल्कि उनके संरक्षण और रखरखाव की भी प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि इस अभियान में स्कूलों, सामाजिक संगठनों और स्थानीय नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। स्वच्छता अभियान भी समीक्षा बैठक का प्रमुख विषय रहा। जिले में 14 जून तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इंचार्ज सचिव पी. स्वरूप ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किर और ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई कार्यों को युद्धस्तर पर संचालित किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से सड़कों के किनारे जमा कचरे, प्लास्टिक अपशिष्ट और नालों में जमा गंदगी को तत्काल हटाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान जलभराव और जलनिकासी संबंधी समस्याओं का एक प्रमुख कारण प्लास्टिक कचरा और अव्यवस्थित सफाई व्यवस्था होती है। यदि समय रहते सफाई कार्य पूरे कर लिए जाएं तो कई संभावित समस्याओं को रोका जा सकता है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि शहर के साथ-साथ गांवों में भी स्वच्छता अभियान को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई कार्य के निदेश दिए गए। बैठक में आगामी मानसून को देखते हुए आपदा प्रबंधन की तैयारियों की भी गहन समीक्षा की गई। इंचार्ज सचिव ने

जिले में उपलब्ध संसाधनों, राहत एवं बचाव उपकरणों तथा विभिन्न आपदा प्रबंधन एजेंसियों के साथ समन्वय की स्थिति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) के साथ सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। समन्वय को मजबूत बनाए रखने के निर्देश दिए ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। विशेष रूप से नदी किनारे बसे गांवों और बाढ़ संभावित क्षेत्रों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों से अलर्ट सिस्टम, संचार उपकरणों के निदेश दिए गए। बैठक में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि निवेश, उद्योग और विकास से जुड़े कार्यक्रमों को व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से आयोजित किया जाए ताकि जिले की विकास संभावनाओं को रोजिडेंट अतिरिक्त कलेक्टर बी.एस. पटेल, उप वन संरक्षक तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के अंत में इंचार्ज सचिव पी. स्वरूप ने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और यह सुनिश्चित करें कि राज्य सरकार की योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ समय पर जनता तक पहुंचे।

को जागरूक करने और स्कूलों में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। बैठक में विकसित भारत की अवधारणा को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई। प्रगतिपथ यात्रा, प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन, जनकल्याण शिविर, विकसित भारत संकल्प सम्मेलन और प्राकृतिक खेती कार्यशालाओं को लेकर तैयारियों का जायजा लिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि इन कार्यक्रमों में अधिकतम जनभागीदारी सुनिश्चित की जाए ताकि नागरिकों को सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी मिल सके। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को लेकर भी प्रशासनिक तैयारियों पर चर्चा हुई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जिले में बड़े पैमाने पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएं और लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों और सामाजिक संस्थाओं को इस अभियान से जोड़ने पर भी जोर दिया गया।

अहमदाबाद मण्डल की आत्मनिर्भर पहल: तीन नए वाणिज्यिक अनुबंधों से बदलेगी सुरक्षा, सफाई और सफर की सूरत ई-नीलामी के जरिए गैर-प्रीमियम ट्रेनों में वेंडिंग, मालिया गुड्स शेड में वैगन सफाई और वंदे भारत विज्ञापनों के लिए 3 साल के अनुबंध किए जारी

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के वाणिज्य विभाग ने राजस्व के नए स्रोतों को बढ़ाने और परिचालन दक्षता में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, 1 जून 2026 को तीन महत्वपूर्ण ई-ऑक्शन (e-auction) अनुबंधों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। 3 वर्षों की अवधि के लिए दिए गए ये अनुबंध यात्री सुविधा, माल ढुलाई लॉजिस्टिक्स और प्रीमियम ब्रांडिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हैं, जो सामूहिक रूप से 4.47 करोड़ का गैर-क्रियाय राजस्व (Non-Fare Revenue - NFR) प्रदान करेंगे। इन निविदाओं के माध्यम से रेलवे प्रशासन द्वारा बिना किसी पूंजीगत निवेश या परिचालन व्यय के, रेलवे खजाने में कुल 4.47 करोड़ का सीधा वित्तीय योगदान सुनिश्चित हुआ है।



1. सफर के अनुभव में बदलाव: ट्रेन साइड वेंडिंग (ट्रेन के भीतर बिस्की)-(अनुबंध राजस्व: 3.72 करोड़): गैर-प्रीमियम ट्रेनों में ‘ट्रेन साइड वेंडिंग’ अनुबंध का मुख्य उद्देश्य यात्रियों के लिए एक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुविधाजनक व्यवस्था स्थापित करना है। यात्रियों के लिए बेहतरीन सुविधा: यात्रियों को अब सफर के दौरान अपनी सीट पर ही आवश्यक दैनिक सामान आसानी से मिल सकेगा। इसमें दूधपेस्ट, दूधब्रश, डिश, सैनिटरी पैड, डायपर, समाचार पत्र, त्रिकोण, मोबाइल चार्जर, इंयरफोन और खिलौने जैसी वस्तुएं शामिल होंगी। यात्री हितों की सुरक्षा: यात्रियों से अधिक वसूली को रोकने के लिए सभी उत्पादों को अनिवार्य रूप से अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर बेचा जाएगा। इसके साथ ही बिल/रसीद देना अनिवार्य होगा और किसी भी एक्सचेंज या अनधिकृत उत्पाद को रिजिडेंट अतिरिक्त कलेक्टर बी.एस. पटेल, उप वन संरक्षक तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के अंत में इंचार्ज सचिव पी. स्वरूप ने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और यह सुनिश्चित करें कि राज्य सरकार की योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ समय पर जनता तक पहुंचे।

तहर सत्यापित, निर्धारित वर्दी और बैच में होंगे तथा उनके पास QR कोड आधारित पहचान पत्र होंगे। डिजिटल एकीकरण: यात्रियों को यात्रा के दौरान ऑनलाइन ऑर्डर और डिलीवरी की सुविधा भी मिलेगी, जिससे उनका यात्रा अनुभव और अधिक सुगम बनेगा। 2. बुनियादी ढांचे की मजबूती: मालिया (MALB) गुड्स शेड में वैगन सफाई-(अनुबंध राजस्व: 0.57 करोड़): मालिया गुड्स शेड में वैगन सफाई का यह अनुबंध एक आत्मनिर्भर मॉडल पर आधारित है, जो रेलवे की लागत को कम करते हुए कांथस्थल की स्थिति में सुधार करता है। रेलवे के खर्च की बचत: वैगनों और गुड्स शेड परिसर की सफाई का पूरा खर्च ठेकेदार द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा, जिससे रेलवे के अपने सफाई खर्च में सीधी बचत होगी। टैक और वैगन की लंबी उम्र: कोयले और

अन्य अवशेष सामग्रियों की नियमित सफाई से वैगनों और ट्रैक की उम्र (लाइफस्पैन) बढ़ेगी। यह गुड्स शेड परिसर में कचरा जमा होने से भी रोकेगा, जिससे कर्मचारियों के लिए सुरक्षित कामकाजी माहौल तैयार होगा। सस्टेनेबल कर्मशियल मॉडल: इस अनुबंध के तहत ठेकेदार को सफाई के दौरान निकलने वाले अवशेष (जैसे कोयला) को इकट्ठा कर बेचने की अनुमति होगी, जिससे यह मॉडल ठेकेदार के लिए भी आर्थिक रूप से व्यावहारिक और टिकाऊ बना रहेगा। 3. ब्रांडिंग को नया आयाम: वंदे भारत हेंड रेस्ट कवर पर विज्ञापन-(अनुबंध राजस्व: 0.18 करोड़): देश की प्रीमियम सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की लोकप्रियता का लाभ उठाते हुए, इस अनुबंध के तहत कोच के भीतर उपलब्ध स्पेस का उपयोग ब्रांड विजिबिलिटी के लिए किया जाएगा।

आकर्षक और आधुनिक लुक: ब्रांडेड हेंड रेस्ट कवर से ट्रेन के कोच के अंदर का माहौल अधिक साफ-सुथरा, एकसमान और पेशेवर दिखाई देगा, जो यात्रियों के सफर को और सुखद बनाएगा। विज्ञापनों और रेलवे दोनों को लाभ: सस्टेनेबल कर्मशियल मॉडल: इस अनुबंध के तहत ठेकेदार को सफाई के दौरान निकलने वाले अवशेष (जैसे कोयला) को इकट्ठा कर बेचने की अनुमति होगी, जिससे यह मॉडल ठेकेदार के लिए भी आर्थिक रूप से व्यावहारिक और टिकाऊ बना रहेगा। 3. ब्रांडिंग को नया आयाम: वंदे भारत हेंड रेस्ट कवर पर विज्ञापन-(अनुबंध राजस्व: 0.18 करोड़): देश की प्रीमियम सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की लोकप्रियता का लाभ उठाते हुए, इस अनुबंध के तहत कोच के भीतर उपलब्ध स्पेस का उपयोग ब्रांड विजिबिलिटी के लिए किया जाएगा।

भारतीय रेल पर पहली बार रनिंग रेल लाइन पर रोड क्रॉलर क्रेन द्वारा हैवी एवं लम्बे स्टील ओपन वेब गर्डरों का सफल प्रतिस्थापन वडोदरा मंडल की उपलब्धि

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल द्वारा अहमदाबाद-वडोदरा रेलखंड पर महिसागर नदी के ऊपर स्थित ब्रिज संख्या 624 के सभी 8 स्पैनों के री-गार्डरिंग कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। यह भारतीय रेल के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जहाँ रनिंग रेल लाइन पर 67.5 मीटर स्पैन तथा लगभग 320 टन वजनी स्टील ओपन वेब गर्डर का 600 टन एवं 800 टन क्षमता की रोड क्रॉलर क्रेनों की सहायता से प्रतिस्थापन भारतीय रेल में पहली बार किया गया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के दौरान 265 तहसील स्तरीय कार्यक्रमों के माध्यम से 1.53 लाख से अधिक पौधे नि:शुल्क वितरित किए जाएंगे। साथ ही तहसीलों में 861 निर्धारित स्थलों पर वन विभाग के मार्गदर्शन में अतिरिक्त 4.15 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। वन विभाग ने राज्य के प्रत्येक नागरिक, सामाजिक संस्थाओं तथा युवाओं से अपनी माता के नाम पर कम से कम एक वृक्ष लगाने और उसके संरक्षण करने के लिए अनुरोध किया है।

नर्मित यह पुल महिसागर नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण रेलवे संरचना है। नदी में वर्षभर जल प्रवाह रहने के कारण इस पुल पर री-गार्डरिंग का कार्य अत्यंत चुनौतीपूर्ण था। परियोजना के अंतर्गत 67.5 मीटर लंबे तथा लगभग 320 टन वजनी स्टील ओपन वेब गर्डरों का प्रतिस्थापन किया गया। इस महत्वाकीर्णी परियोजना को दो चरणों में पूरा किया गया। प्रथम चरण में पुल के मध्य स्थित 6 स्पैनों के गर्डरों का प्रतिस्थापन कार्य इन्जीनियरिंग दक्षता, नवाचार और टीम भावना का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने बताया कि यह कार्य अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में, निर्धारित समयसीमा के भीतर तथा न्यूनतम बर्खाकों में पूरा किया गया है। इसके लिए उन्होंने इस कार्य से जुड़े ब्रिज, टीआरडी, पी-वे, ऑपरेटिंग, इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल विभागों के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अविश्वसनीय सफलता के लिए बधाई दी। **जलप्रवाह ने बनाया कार्य चुनौतीपूर्ण:** वर्ष 1913 में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान

डन सुपर-लिफ्ट व्यवस्था उपलब्ध थी। नदी के भीतर क्रेनों की स्थापना हेतु विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए सैंड पंप को बड़े बोट पर स्थापित कर लगभग 30 मीटर ऊंचा कुविम सैंड वेड तैयार किया गया। इसी प्लेटफॉर्म पर क्रेनों को स्थापित कर गर्डरों का प्रतिस्थापन कार्य सुरक्षित एवं सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। पुल के दोनों एंड स्पैनों पर स्थान की कमी के कारण दो क्रेनों की तेनती संभव नहीं थी। इस चुनौती का समाधान करते हुए इंजीनियरों ने 800 टन क्षमता की क्रॉलर टायर रोड क्रेन का उपयोग कर एंड स्पैनों के गर्डरों का प्रतिस्थापन किया, जिसमें 300 टन सुपर-लिफ्ट व्यवस्था लगी हुई थी। इस अभिनव तकनीक के प्रयोग से लागत, ट्रैफिक ब्लॉक एवं पावर ब्लॉक में उल्लेखनीय बचत हुई। यह परियोजना उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, किसी भी रेलवे पर रोड क्रेन का उपयोग को हराते बड़े स्पैन के स्टील ओपन वेब गर्डर का री-गार्डरिंग कार्य पूर्व में नहीं किया गया है। महिसागर नदी पुल की री-गार्डरिंग परियोजना का सफल समापन पश्चिम रेलवे के आधारभूत संरचना उन्नयन कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिससे अहमदाबाद-वडोदरा रेलखंड पर सुरक्षा, विश्वसनीयता एवं परिचालन क्षमता में और अधिक वृद्धि होगी।

विश्व पर्यावरण दिवस : 5 जून

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के करकमलों से गुजरात में ‘एक पेड़ मां के नाम 3.0’ महाअभियान का गांधीनगर से शुभारंभ किया जाएगा

► **‘एक पेड़ मां के नाम 3.0’ अंतर्गत राज्यभर में पहले ही दिन 6 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा**
► **प्रकृति के संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री की पहल : गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र को ‘हरियाली लोकसभा’ बनाने के लिए वन विभाग द्वारा लगभग 500 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में 50 लाख से अधिक पौधे लगाकर ‘वन कवच - माइक्रो फॉरेस्ट’ तैयार किया जाएगा**

गांधीनगर : कल यानी कि 05 जून ‘विश्व पर्यावरण दिवस’ पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से प्रेरित ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ होगा। गांधीनगर से मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के करकमलों से राज्यव्यापी अभियान का आरंभ किया जाएगा। गांधीनगर के ‘ज’ रोड पर लोकभवन स्टाफ क्वार्टर्स के पास 0.5 हेक्टेयर क्षेत्र में ‘वन कवच’ पद्धति से

लगभग 5,000 पौधों का रोपण कर यह राज्यव्यापी अभियान शुरू किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2024 में नई दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क से ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान का शुभारंभ किया गया था। इस वन विभाग के अनुसार वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री अर्जुन मोदवाडिया तथा राज्य मंत्री श्री प्रवीण माळी के मार्गदर्शन में समग्र

राज्य में इस अभियान को गतिमान बनाया जाएगा। पर्यावरणीय संतुलन और जैव विविधता (बायोडायवर्सिटी) के संरक्षण के लिए गांधीनगर में 57 स्थानीय प्रजातियों के पौधों का रोपण किया जाएगा। जो कि त्रि-स्तरीय होगा। जिसमें 16 प्रजातियों के 20 प्रतिशत उच्च स्तरीय पौधें, 25 प्रजातियों के 50 प्रतिशत मध्यम स्तरीय तथा विभिन्न 16 प्रजातियों के 30 प्रतिशत निम्न स्तरीय पौधों का समावेश होगा। इस वन कवच (माइक्रो फॉरेस्ट) की विशेषता यह है कि यह बहुत कम स्थान में अत्यंत सघन तथा तेजी से विकसित होने वाला शहरी जंगल तैयार करता है। इसके अतिरिक्त, वन विभाग के अनुसार इस अभियान अंतर्गत केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री तथा गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री अमित शाह के लोकसभा क्षेत्र को ‘हरियाली लोकसभा’ बनाने के

लिए वन विभाग द्वारा लगभग 500 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में 50 लाख से अधिक पौधे लगाकर ‘वन कवच - माइक्रो फॉरेस्ट’ तैयार किया जाएगा। **विश्व पर्यावरण दिवस : वृक्षारोपण की माइक्रो प्लानिंग** ‘विश्व पर्यावरण दिवस’ से शुरू कर आगामी सप्ताह तक वन विभाग द्वारा पूरे गुजरात को कवर करने वाले विभिन्न जन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जो कि इस प्रकार हैं : राज्यभर में ग्रामीण एवं शहरी स्तर पर कुल 50 हजार ‘समूह स्तर’ निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक समूह द्वारा 12 पौधों का रोपण किया जाएगा और एक ही दिन में पूरे राज्य में 6 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा। **8 जून से 14 जून 2026: पर्यावरण सप्ताह** इस सप्ताह के दौरान प्रत्येक जिला स्तर पर मुख्य चार कार्यक्रम तथा